उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग – 1 देहरादून : दिनांक :0्री ाहुरा, 2023

## कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474/02(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2019 के द्वारा शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं आदि की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त समिति के गठन, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2— तत्क्रम में योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया में गतिशीलता लाए जाने एवं समय से साथ परिवर्तनीय बाजार दरों को संज्ञान में रखते हुए व्यय वित्त समिति के कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 के कितपय प्रस्तरों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकित प्रदान करते हैं: —

निम्नवत संशा	शाधित किए जीन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : —		
कार्यालय ज्ञाप	वर्तगान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	
दिनांक			
01.8.			
2019 का			
प्रस्तर संख्या			
2A		राज्य सरकार द्वारा व्ययभार वहन किये	
	योजनायें / परियोजनाथें, जिसमें सगस्त	1	
		योजनायें / परियोजनायें, जिनमें किसी एक	
3		इकाई पर रू 1.00 करोड़ या उससे अधिक	
		का वार्षिक आवर्तक़ व्यय अथवा रू 10.00	
		करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय निहित	
	-	हो, तो ऐसे प्रस्ताव अनिवार्यतः व्यय वित्त	
		समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये	
	प्रस्ताव अनिवार्यतः व्यय वित्त समिति के	जायेंगे।	
	समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेगे।		
2C		CSS के अन्तर्गत कोई योजना जो पूर्व से	
	से चल रही हो (On Going	चल रही हो (On Going Scheme)	
	Scheme) सामान्यतः व्यय वित्त	सामान्यतः व्यय वित्तं समिति की परिधि से	
	समिति की परिधि से आच्छादित नहीं	आच्छादित नहीं होंगी। परन्तु इस प्रकार की	
	होंगी। परन्तु इस प्रकार की योजना का	योजना का ऐसा घटक, जो नई परियोजना	
	ऐसा घटक जो नई परियोजना हो एवं	हो एवं उस पर रू 1.00 करोड़ या उससे	
	उस पर रू .50.00 लाख का वार्षिक	अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू	
		10.00 करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय	
	उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित	निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त	
	हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति	सगिति की परिधि से आच्छादित होंगे।	
	की परिधि से आच्छादित होंगे।		
		(उदाहरण—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के	
	(उदाहरण–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	अन्तर्गत पूर्व से चल रही (On Going	
		Scheme) NHM स्कीम सामान्यतः व्यय	
Ţ		,	

	रामान्यतः व्यय वित्तं सामातं का पारिष्ट से आच्छादित नहीं होंगी, परन्तु उक्त योजना (Scheme) के अन्तर्गत कोई नया अस्पताल बनाया जाता है, जिस् पर रू 50.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रू 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्तं समिति की	
2F	अनावर्तक कार्यो / परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन यदि मूल अनुमानों से 50 प्रतिशत से अधिक हों तो पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण / तकनीकी परीक्षण एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के माध्यम से ही किया जायेगा तत्पश्चात वित्त विभाग वित्तीय स्वीकृति संबंधित कार्यवाही करेंगे।	रू० 6.00 करोड़ से अधिक के ऐसे अनावर्तक कार्यों / परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन यदि मूल अनुमानों से 50 प्रतिशत अथवा रू 10.00 करोड़ (दोनों में से जो धनराशि कम हो) से अधिक हों तो पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण / तकनीकी परीक्षण एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के माध्यम से ही किया जायेगा। तत्पश्वात वित्त विभाग वित्तीय स्वीकृति संबंधित कार्यवाही करेंगे।
2H	की परिधि में न आने वाले किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी परीक्षण हेतु व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। व्यय वित्त समिति की परिधि में मात्र निर्माण/विकास कार्यों विषयक परियोजनायें ही नहीं आयेंगी, वरन रू 5. 00 करोड़ या अधिक की सभी नई योजनाओं / परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ सन्दर्भित किया जाना चाहिये जब तक कि वित्त विभाग से किसी विशिष्ट योजना को छोडने का अनुमोदन न दिया गया हो।	विशेष परिस्थितियों में व्यय वित्त समिति की परिधि में न आने वाले किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी परीक्षण हेतु व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। व्यय वित्त समिति की परिधि में मात्र निर्माण / विकास कार्यों विषयक परियोजनायें ही नहीं आयेंगी, बल्कि रू 10.00 करोड़ से अधिक की सभी नई पूंजीगत एवं राजस्व पक्ष से सम्बन्धित योजनाओं / परियोजनाओं (कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों को छोड़कर) को व्यय वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ सन्दर्भित किया जायेगा, जब तक कि वित्त विभाग से किसी विशिष्ट योजना को छोड़ने का अनुमोदन न दिया गया हो।
	की योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्ताव / आगणन जिनकी लागत रू. 1. 00 करोड़ से अधिक तथा रू 5.00 करोड़ से कम हों, को प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। इस प्रकार की विभागीय	व्यय वित्त समिति की परिधि से बाहर की योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्ताव / आगणन, जिनकी लागत रू 1.00 करोड़ से रू 10.00 करोड़ तक हों, को प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या 474 दिनांक 01.8.2019 में निर्दिष्ट बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। इस प्रकार

अंतर्गत राज्य योजना आयोग के की विभागीय वित्त समिति की बैठक में तकनीकी अभियंताओं को अनिवार्य रूप वित्त विभाग के अधिकारियों को एवं से आमंत्रित किया जायेगा और विभागीय नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना समिति द्वारा उनके सुझावों का संज्ञान आयोग के तकनीकी अभियंताओं को लेते हुए बैठक का कार्यवृत्त निर्गत अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जायेगा। किया जायेगा। विभागीय समिति के वित्त एवं नियोजन विभाग के प्रतिनिधियों समक्ष 'परिशिष्ट-क' के अनुसार प्रस्ताव द्वारा विभागीय वित्त समिति की बैठक में वित्त एवं नियोजन विभाग के परीक्षण के बिन्दुओं का समाधान कराया जायेगा और प्रस्तुत किया जायेगा। विभागीय वित्त समिति द्वारा उनके सुझावों का संज्ञान लेते हुए बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया जायेगा। विभागीय समिति के समक्ष उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या ४७४ दिनांक 01.8.2019 के 'परिशिष्ट-क' के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। आगणनों की TAC से सम्बन्धित व्यवस्था प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर TAC 4(4) क्त 1.00 करोड़ से अधिक के आगणनों का तकनीकी परीक्षण पूर्व की भांति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रभावी रहेगी। तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ट (TAC) द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0—156 दिनांक 24.02.2015 एवं शासनादेश सं0-359, दिनांक 23.03.2015 में दी गयी व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। इनमें से रू 5.00 करोड़ अथवा इससे अधिक के आगणनों का तकनीकी परीक्षण तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) से किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण व्यय वित्त समिति द्वारा किया जायेगा।

उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मात्र उक्त सीमा तक संशोधित समझा Signed by Dilip Jawalkar जाएगा।

Date: 31-05-2023 10:55:47 (दिलीप जावलकर) सचिव।

संख्या : 1260371) / XXVII (1) / 2023 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
- 6— महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।



1/126032/2023 1/126032/2023

7— आयुक्त, कुमाऊं / गढवाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी ।

8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10— मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शारान को मा, मंत्रिमण्डल के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी उनके पत्र संख्या 4/2/IX/XXI/2023-CX दिनांक 19 मई, 2023 के क्रम में।

11- राज्य योजना आयोग/नोडल विभाग।

12- गार्ड फाइल।

( दिलीप जावलकर ) सचिव।